THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Please wind up. समाप्त कीजिए।

श्री विजय कुमार रूपाणी: इसके ऊपर भी काम कीजिए, तो ठीक रहेगा। धन्यवाद।

MESSAGE FROM LOK SABHA—Contd.

The Central Road Fund (Amendment) Bill, 2007.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Central Road Fund (Amendment) Bill, 2007, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 16th May, 2007."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

The Electricity (Amendment) Bill, 2007—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Shri Rajniti Prasad. Please take only five minutes.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें समय दिया।

महोदय, बहुत-सारे वक्ताओं ने यहां पर बोला है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलता हूं और हमारी समझ में आता है कि अभी रूपाणी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वहां 24 घंटे बिजली रहती है। तो इस पर पार्लियामेंट की एक कमेटी बनानी चाहिए, जो रिसर्च करे, वहां पर जाकर देखे कि क्या बात है? क्यों ऐसा होता है? हमें लगता है कि वहां पर 24 घंटे में कभी बिजली नहीं जाती है। तो क्या जब वहां दंगा हुआ था, उस वक्त भी बिजली नहीं गई थी? मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे बिजली, पूरे हिन्दुस्तान में, even in Parliament, even in Delhi, जहां हम रहते हैं, वहां भी 24 घंटे नहीं रहती, एक-दो मिनट इधर-उधर हो जाता है। अत: किसी के बारे में अगर ज्यादा कुछ कहना है तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, जिससे लगे कि आप उनके मामले को कुछ ज्यादा कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह जो बिल आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। वह अच्छा है, लेकिन मुझको एक डर है। वह डर यह है--हिन्दी में एक साधारण-सी कविता है कि ''माया में दोनों गए, माया मिली न राम''। जो उन्होंने दिया है ...(व्यवधान)... हां, माया में दोनों गए, माया मिली न राम। तो joint responsibility of the state दिया है ...(व्यवधान)... हां, हां मैं बता रहा हूं ...(व्यवधान)... माया का मतलब होता है-माया। वह माया नहीं, जो आप कह रहे हैं ...(व्यवधान)... स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की एक ज्वायंट रेस्पोंसिबिलिटी दी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने दोनों का दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की रिस्पोंसिबिलिटी को दोनों को ज्वायंट में दे दिया, तो अब हर आदमी शिफ्ट करेगा और वह कहेगा कि ठीक है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। इसलिए या तो वहां आपकी मशीनरी फिट होनी चाहिए, पूरी मशीनरी फिट होनी चाहिए, तो दोनों मिल कर काम करेंगे। वरना केवल कानून बना देने के बाद यह मामला नहीं आएगा।

दूसरी बात, आपने जो इसमें टेम्परिंग के बारे में दिया है। टेम्परिंग के लिए जो सेक्शन 13 में 135 प्रिंसिपल एक्ट सब सेक्शन वगैरह जो आपने दिया है, उसके बारे में हमको यह कहना है कि इसमें जो बड़े लोग हैं, जो कारखाने चलाते हैं, बड़े-बड़े कारखाने चलाते हैं, वहां ही टेम्परिंग होते हैं, वहीं उनकी बचत होती है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि उपसभाध्यक्ष जी, कि मुझको कभी-कभी लगता है कि बिहार में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, जहां पर 60 वर्षों के बाद भी बिजली नहीं गई है। बिजली का खम्भा भी नहीं गया है। अगर बिजली का खम्भा नहीं गया है, बिजली नहीं गई है तो आजादी का मतलब क्या है, महोदय? 60 सालों बाद भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जहां पर बिजली नहीं गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर गांवों में बिजली नहीं गई है, तो शहरों की हालत भी अच्छी नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: 60 में से 15 आपका ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Mr. Pany, this is not correct.

श्री राजनीति प्रसाद: सर, बिहार के शहरों में भी यह मामला अच्छा नहीं है। हम लोग पटना में रहते हैं। वहां तीन-तीन घंटे, चार-चार घंटे बिजली गायब रहती है, बिजली नहीं रहती है और अगर हम इन्वर्टर लगाते हैं, तो इन्वर्टर भी काम नहीं करता है। मंत्री जी ने कानून बना दिया, अमेंडमेंट ला दिया और इसमें बहुत सेक्शन बना दिए, कहा कि आप पूरी मजबूती से काम करेंगे और फाइन करेंगे, लेकिन जो चार-चार घंटे बिजली नहीं रहती, उसके बारे में आप क्या करेंगे? गांवों में तो स्थिति यह है कि बिजली भी नहीं होती और वहां लोगों को मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता कि

लालटेन जलाकर बच्चे पढ़ सकें। ये दोनों स्थिति गंभीर हैं। इसीलिए मेरा यह कहना है कि आपने इसमें पीनल प्रोविजन रखा है, लेकिन आप ऐसा कुछ करिए, जिससे गांवों तक बिजली जाए। गांवों में बिजली जाने का कारण यह है, जैसा कि उन्होंने कहा है, हर दिशा में...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): आप कनक्ल्यूड करिए।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, क्या समय खत्म हो गया? दो मिनट, सर।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी. जे. कुरियन): नहीं, एक मिनट।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, जिस गांव में बिजली नहीं है, उसके बारे में छोड़ दीजिए, लेकिन जिस गांव में थोड़ा-बहुत बिजली का साधन है भी, वहां भी बिजली नहीं आती है। वहां पोल हैं, पूरी लाइन है, मगर बिजली आती नहीं है और अगर कभी-कभी बिजली आ जाती है, तो लोग पूजा की दृष्टि से देखते हैं कि आज गांव में बिजली है।

[श्री उपसभापति पीठासीन हुए]

उपसभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि कानून आपने बनाया है, बहुत अच्छा कानून है, मगर हमारे यहां जो सिंक थर्मल पावर हैं, जो बहुत सारे हैं, उनके बारे में भी आप कुछ सोचिए। इन सिंक थर्मल पावर के जो यूनिट हैं, जो जनरेटर्स हैं, उनको ठीक कराइए, उनसे बिजली का उत्पादन ज्यादा कराइए, जिससे हम लोगों को बिजली मिल सके और हमारे गांवों में बिजली पहुंच सके।

आपने मुझे समय दिया, मेरा समय नहीं था, मेरी पार्टी का भी समय नहीं था, फिर भी समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सम्माननीय उपसभापति महोदय, मैं उन सभी 12 माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस बिल पर बहस की है, आभार प्रदर्शित करता हूं। उन्होंने कुछ सूचनाएं भी दीं, उनका भी स्वागत करता हूं।

महोदय, दोनों तरफ से जिस तरह से इस बिल पर बहस हुई, उसमें एक तो भारत की पावर की परिस्थिति क्या है, उस बारे में भी उन्होंने बताया और उसमें क्या मैजर्स लेना चाहिए, वे भी बताएं। इसके साथ ही सरकार ने किस प्रकार की भूमिका ले ली है, उसका भी यहां समर्थन किया है। सम्माननीय सदस्य श्री अजय मारू जी ने डिबेट की ओपनिंग की। मैं उनके द्वारा दी जा रही सभी फिगर्स देख रहा था, मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया और ऐसा लग रहा है कि वह मेरी वेब-साइट पर भी गए हैं, क्योंकि उन्होंने जैसी फिगर्स दी है। इसके लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम लोग वेब-साइट पर जाते हैं। चाहे पावर फाइनेन्स कारपोरेशन हो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो या पावर का हो या हमारी परचेज ट्रेडिंग का हो, वह सब हमारी वेब-साइट पर

हमने लगाया हुआ है और आज देश में पावर की स्थिति क्या है, वह जानकारी भी हमने देश को बताने के लिए वहां लगाई हुई है। हमने कुछ छुपाया नहीं है, ट्रांसपेरेन्सी हमने रखी है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने, माननीय सदस्य ने कहा कि यह सब्जेक्ट कैसा है? एक तो यह कन्करेंट सब्जेक्ट है और भारत सरकार उनके प्रयासों में सप्लीमेंटरी है। जो स्टेट की जिम्मेदारी है, जो कन्करेंट है, वह जिम्मेदारी आज तक हम पहचानते नहीं रहे हैं। हमने देखा, जिसका जिक्र माननीय सदस्य अजय मारू जी ने किया कि सेवेन्थ प्लान, एट्थ प्लान, नाइन्थ प्लान, टेन्थ प्लान, इन सबको देखा जाए, तो स्टेट ने यहां कितना पावर जनरेशन किया, कैपेसिटी एडिशन में क्यों शॉर्टेज आ गया है? स्विच-ओवर करने से पहले मैं केवल यह बताऊंगा कि जो आरोप महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में हो गया, उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा, फिर डिटेल में जाऊंगा, क्योंकि यह कन्करेंट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं पहले बताऊंगा।

उपसभापति जी, फरवरी, 2006 में allocation of Gujarat was reduced by 151 megawatts, जो 208 बोलते हैं, उतना नहीं है, उसमें से 101 to Maharashtra and 50 megawatts to Dadra Nagar Haveli दे दी थी। अब, उपसभापति जी, जरा देखिए कि सिचुएशन क्या है। महाराष्ट्र में energy shortage था 24%, यानी 2,326 मिलियन यूनिट्स, पीकिंग शार्टेज था 29.5%, that is, 4,745 megawatts और स्थिति क्या थी, कहां से कितना पावर लेते थे? Power purchased from other States is 514 million units, withdrawal from the grid is 161 megawatts. यह महाराष्ट्र का है। अब गुजरात का बताता हूं। गुजरात में energy shortage is 6.1 per cent, that is, 307 million units, पीकिंग शार्टेज 8.2, that is, 683 megawatts. राज्य की यह परिस्थिति होते हुए भी क्या वे बाहर से बिजली परचेज करते थे? नहीं। Sale to other States is 92 millions units. इतनी कम, शार्टेज होते हुए भी बाहर बिजली बेचते हैं, इसका कारण यह था कि आपकी बिजली उतनी नहीं लगती थी और जिसको जरूरत थी बिजली की, उनको बेचते थे, यह तो हम हमेशा देखते हैं और अंडर विदड्रावल कितना था आपका ग्रिड से-124 मिलियन यूनिट्स जनवरी, 2006 में, जब मैं आया था, उसी महीने में मैंने 55 megawatts गुजरात को रिटर्न किया। थोड़ी सी स्थिति महाराष्ट्र की ठीक हो गई थी। हमारे जो पांच लोड सैंटर्स हैं, इस पर हम यह निगाह रखते हैं कि जहां बिजली कम है, जहां बिजली जरूरी है, वहां हम उन लोड सैंटर्स से पहुंचाने का काम करते हैं। यह बात सही है कि केवल गुजरात ही नहीं, जहां बिजली कम है वहां भी हम हमेशा देते हैं। अभी हमने कहलगांव का उद्घाटन किया। यह बात सही है कि कहलगांव में, टोटल बिहार में पर कैपिटा कंजम्शन खाली 75 है। ...(व्यवधान)... देश का, यह 612 नहीं है, यह 666 है। आपने चाइना का बोला, लेकिन अमेरिका का आपने नहीं बोला, उसका 21,000 पर कैपिटा कंजम्शन है-21,000 से 22,000 है, चाइना का 1900 है। यदि वह देखा जाए तो हमारा कैपेसिटी ऐडिशन, जो राज्य का काम

है, वह हम नहीं कर पाते हैं। जो हमारे NTPC Units हैं, NHPC Units हैं, यह एक ऐसा हो गया कि देश की बिजली बनाने का काम राज्यों का है, वह हम नहीं करेंगे, तो केवल भारत सरकार ही बनाए, इस प्रकार का काम हो रहा है। उपसभापति जी, मैंने यह देखा कि इसका कारण क्या है? यह हम सबके लिए चिंता का विषय है, कौन किस पार्टी का है, किस प्रांत का है, यह सोच नहीं है, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय यह है कि क्यों हमारा इस तरह से नुकसान हो रहा है। जिस राज्य में 6,000 megawatts की शार्टेज है, वह राज्य वाला यहां आकर अपना प्रोजेक्ट लेकर जाता था खाली तीन या चार हजार megawatts तक का और आप राज्य में जाकर करता कितना था, एक हजार या पांच सौ megawatts का। इसमें बहुत डेफिसिट है, जो पिछले दस साल में बढ़ता गया ओर सब राज्य इसमें शामिल हैं। एक उड़ीसा की बात मैं कहना चाहता हूं कि उनकी पोजीशन थोड़ी ठीक है, मैं उड़ीसा का अभिनन्दन करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इतना बड़ा घाटा होता है। मैं T&D losses बताना चाहता हूं कि 2001-02 में 38.86 हमारे T&D losses हैं, अभी 2005-06 में यह 34.54 हो गए हैं और हम इसको उससे भी कम कर रहे हैं। अभी हम 15 परसैंट तक यह T&D losses लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हायर पावर है, जैसे अभी एपीडीआरपी का उल्लेख भी किया है। यह अच्छी बात है कि उड़ीसा या गुजरात ने पैसा उठाया और अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सब राज्य ऐसा करें, लेकिन वास्तविक परिस्थिति क्या है, यह अवश्य जानना चाहिए। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, मैं आपके सैक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर लार इलेक्ट्रिसिटि ऐक्ट पर भी आऊंगा, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि वहां पर बिजली नहीं दी गई, गैस नहीं दी गई, जब गैस नहीं मिलती है तो एग्रीमेंट ही क्यों किया? इस देश में जुलाई 2008 तक गैस मिलने वाली भी नहीं है, ऐसे में अगर आप सिर्फ जनता को दिखाने के लिए यह एग्रीमेंट करते हैं तो गैस कैसे मिल जाएगी? ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र भाटिया (उत्तर प्रदेश): गैस तो आपने दी ही नहीं ...(व्यवधान)... रिकार्ड पर ...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार शिन्दे: नहीं, नहीं, रिकॉर्ड पर आकर क्या एनटीपीसी को भी मिल सकता है? इस सदन में मैंने बहुत बार रिप्लाई दिया है और, उपसभापति महोदय, मजे की बात यह है, मैं आपको क्या बताऊं, इनका एक अनपारा प्रोजैक्ट है, वहां पर जैपनीज लोग मदद करने वाले थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें नहीं करवाना है, हम खुद ही देखेंगे। जब दूसरा देश वहां पर आ कर लोन देने के लिए तैयार है तब आपने ही रिफ्यूज किया और उसे गैस वालों को दे दिया ...(व्यवधान)... मैं तो बता रहा हूं ...(व्यवधान)...

देखिए, मैं इस संबंध में दोष नहीं दूंगा, क्योंकि हमें इसे करेक्ट करना है। अगर कल गलती हो भी गई है तो आज उसे करेक्ट करने की बात सोचनी चाहिए, इसलिए हम हर स्टेट को इसी नजरिए से देख रहे हैं कि वहां पर कमी है तो क्यों है और जहां पर हम केपेसिटी एडीशन करना चाहते हैं,

उपसभापति महोदय, यह बात सही है, मैं भी स्टेट से ही आता हूं और बहुत साल तक स्टेट में ही मंत्री रहा हूं। मैं जानता हूं कि राज्यों के पास पैसा नहीं होता है और यह बात बिल्कुल सही है कि वहां पर पैसे की काफी शॉर्टेज रहती है। मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताऊं, 1992 तक मैं वहीं पर फाइनांस मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर था। उस समय हम वहां पर अपनी बिजली गुजरात को बेचते थे, कर्नाटक को बेचते थे, आन्ध्र प्रदेश को बेचते थे। उस समय बिजली के मामले में वह इतना सक्षम था, लेकिन अब किसे दोष दिया जाए? मैं पॉलिटिकल दोष नहीं देना चाहता हूं क्योंकि सत्ता की उलट-पुलट तो होती ही रहती है, लेकिन सत्ता में जो भी उलट-पुलट होती है, जहां तक हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर का या ग्रोथ रेट बढ़ाने का संबंध है, उस हम लोग नहीं देखेंगे तब कौन देखेगा? सत्ता में नये-नये व्यक्ति आते हैं, यदि पिछले व्यक्ति ने कुछ नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे, इस तरह काम नहीं होता हैं।

हमारे यहां एक एनरॉन आ गया और जब हम उसी पर आधारित रहे तो एनरॉन भी बोला कि हम तो तुम्हें समुद्र में डुबाएंगे। वह भी नहीं चल रहा था, ऐसे में फिर सत्ता में यूपीए गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने निर्णय ले लिया और फॉरेन के जितने भी लैंडर्स थे, भारत सरकार ने उनका पैसा वापस दे दिया। अभी रत्नागिरि पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। 2150 मैगावॉट का यूनिट है और उसमें से 750 मैगावॉट यूनिट अभी चला रहे हैं। कहा जाता है कि गैस मिलेगी, लेकिन वहां पर भी गैस नहीं है। महाराष्ट्र में भी शॉर्टेज है। अगर गैस मिलती, मैं यह नहीं बोलूंगा कि रूपाणी जी, पाइप का क्या हुआ, वह आपको मालूम है और यह होता रहता है। ठीक है, आपकी दिक्कतें हैं, लेकिन हमने मुख्य मंत्री से बात की तब उसे चालू किया, वह तो काफी दिन बंद था। इसमें हम बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि जो काम करना है, वह तो करना ही है। यदि काम जल्दी हो जाता तो 15-20 दिन पहले ही महाराष्ट्र को बिजली मिल जाती, उससे आपका लोड ही कम हो जाता ...(व्यवधान)

श्री जयन्ती लाल बरोट (गुजरात): जिसके हाथ में डंडा होता है, वह डंडा ले कर घूमता-फिरता रहता है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: नहीं, लेकिन यदि उसमें एक महीना निकल गया तो 1 जून को मिलने वाला काम 25 जून तक चला गया, वही बिजली मैं डायवर्ट करवा सकता था, क्योंकि हम मॉनिटर करते हैं। यहां पर हमारा जो सैंट्रल लोड डिस्पैच सैंटर है, वहां अभी इसे मैनेज किया जा रहा है। इतना ही नहीं बहुत से लोग हमारे लोड सैंटर से परमिशन लिए बिना पावर खींचते थे, लेकिन अभी हमने उसकी कीमत 7.00 या 7.50 रुपये बढ़ा दी है, जिससे उसमें थोड़ा डिसिप्लिन आ गया है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिजली का डिस्ट्रिब्यूशन सबको एक समान होना चाहिए।

उपसभापति महोदय, श्री राजीव गांधी जी के नाम से ग्रामीण विद्युतीकरण शुरू किया गया, यह एक बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश में स्वतंत्रता हासिल करने के साठ

साल के बाद भी कई गांवों या देहातों में बिजली नहीं पहुंच सकी है। इसके लिए कई योजनाएं शुरू की गई खम्भा गांव तक गया, एक लाइट लगाई और ऐसा मान लिया गया कि ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया है। लेकिन राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से बिजली वितरण के जो नियम बनाए गए हैं, उन्हें मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। आपने सजेस्ट किया था कि क्या-क्या होना चाहिए. पहली बात तो यह है वहां पर ग्राम पंचायत को इलेक्ट्रिसिटि दी जानी चाहिए। स्कूल में देनी चाहिए, डिस्पैंसरी में देनी चाहिए, जो कम्युनिटी हॉल हैं उसमें देनी चाहिए। सब पंचायत घर को देनी चाहिए, सभी बी॰पी॰एल॰ को देने को चाहिए। इतना करके सब गांवों में 10 परसेंट बिजली घरों में दे दिया है तभी इसका सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत को देना होगा कि इस गांव में स्कूल हो गया है, चावड़ी हो गई है, पंचायत समिति हो गई है, डिस्पैंसरी हो गई यह सब हो गया है। उसे यह सर्टिफिकेट देना पड़ता है तो रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन उस गांव का हो गया, ऐसा हम मानते हैं नहीं तो नहीं मानते हैं। जैसे यह योजना अप्रैल, 2005 में शुरू हो गई तो आज तक 38,846 देहात हो गए हैं और 9,81,532 हाउसहोल्ड हो गए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं सब बातों, का, मैं बाकी नहीं दूंगा कि कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन किये और क्या है लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि इस सदन में बताया है कि हम 2009 तक ग्रामीण विद्युतीकरण करना चाहते हैं। यह बात सही है कि जहां 300 के ऊपर हेबिटेशन है, देहात हैं उसका काम ले लिया है शुरूआत में। अगर सभी ले लेंगे तो इतना पैसा सरकार के पास नहीं है। अभी जो इसका पूरा एस्टीमेट किया था पहले तो पांच हजार करोड़ मिले थे उसमें करीब-करीब 9 हजार तक के गांव किए हैं। अभी आगे 30 हजार गांव का एस्टीमेट किया है, लेकिन लगता है कि उसमें 50 हजार करोड़ लगेगा। क्योंकि जो एस्टीमेट आ रहे हैं-अभी केरल के हमारे साथी, वहां के दो-तीन डिस्ट्रिक्ट के एस्टीमेट आ गए हैं, जो हमारा नार्म है उससे वन एंड हाफ टाइम उसका एस्टीमेट है, तो वह भी सब देखना पड़ेगा।

श्री के॰बी॰ शणप्पा (कर्नाटक): कर्नाटक के बारे में बतलाइए कि क्या पोजिशन है?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सब के बारे में बताऊंगा, मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता हूं। उपसभपति महोदय, केवल कर्नाटक ही नहीं हमने नॉर्थ ईस्ट भी ले लिया है। कल उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर आए थे उनसे मैंने बात की तथा उनको बताया है कि आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वह सब हम देख रहे है। और उनके देखने के बाद पूरे उड़ीसा को हमने लेना तय किया है। शुरूआत में 4-5 स्टेट ले लिए थे, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है वहां एक्यूट शॉर्टेज था। जो बड़े-बड़े प्रति हैं लेकिन वहां बिजली परसंटेजवाइज बहुत कम है तो वह टार्गेटेड किया और उपसभापति महोदय, इतना काम करने के लिए लोग चाहिए तो हमारे यूटिलिटी से भी हमने लोग दे दिए, पॉवर ग्रिड से लोग दे दिए, एन॰टी॰पी॰सी॰ से दे दिए, एन॰एच॰पी॰सी॰ से दें दिए हैं और दामोदर वैली कारपोरेशन से भी लोग दे दिए हैं ताकि यह काम केवल स्टेट के यूटिलिटि के कांट्रेक्टर ही नहीं हमारे भी लोग करें क्योंकि यह सम्पूर्ण देश का कार्यक्रम है, यह देश के कार्यक्रम में विकास को सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यदि यह

काम करना है तो जैसे पहले यह खम्भे लग गए और उन पर बिजली नहीं आई तो खम्भे उठाकर ले गए ...(व्यवधान)

ये जो गांव हैं, वहां बिजली चाहिए, केवल इस तरह सब को कनेक्शन देकर या ट्रांसफार्मर बिठाकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिजली तो चाहिए। तो यह कौन करेगा? क्या भारत सरकार सब जगह जाएगी। स्टेट की कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? तो स्टेट को भी यह करना होगा। इसके लिए अभी एक महीना पहले स्टेट के सभी पॉवर सैक्रेट्रीज और चीफ सैक्रेट्रीज की बैठक यहां बुलाई और उनसे सब चर्चा की और केपेसिटी एडीशन करने को लगाया और मुझे खुशी इस बात की है कि जब उनको यह सब बताई कि अभी जो उनका डेफिसिट है उसके ऊपर 5 या 10 परसेंट का केपेसिटी एडीशन करने का तय उन्होंने किया है। मुझे इसकी खुशी है। हमने उनको यह भी बोला है कि यह सब कैपेसिटी ऐडिशन करने में आपके पास पैसा नहीं होगा, स्टेट के पास पैसा नहीं होगा, तो हमने पावर फाइनेंस कारपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से, उनको लोन देना तय किया है। अभी-अभी मैंने दो तीन जगह 9-9 सौ करोड़ 2-2 हजार करोड़ के लोन क्लियर किये हैं। हमने इस तरह का काम किया है। 28 तारीख को हमने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलायी है, जिसको हमारे प्रधान मंत्री जी संबोधित करेंगे और केवल पावर के विषय पर दो-तीन ही सब्जेक्ट लेकर इसको कर रहे हैं, उसमें कैपेसिटी ऐडिशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब वार फुटिंग पर, आप सब लोगों को साथ में लेकर काम करना चाहते हैं। यह काम जब तक नहीं करेंगे, तब तक यह शार्टेज बनी रहेगी। जो काम 60 साल में नहीं हुआ है, उसको फिर से हमें कैप्चर करना है, चार-पांच साल में कैप्चर करना है। उपसभापति जी, मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि यह जो कैपेसिटी ऐडिशन में हमारा शार्टेज है, मेरे देश की जो सभी स्टेट्स हैं, उन सभी के मुख्य मंत्रियों के साथ, पावर मिनिस्टर्स के साथ और जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मैंने भाषण किया है, जो आज शार्टेज आने वाली है 78 थाउजेंड मेगावाट की जो है, वह कैपेसिटी ऐडिशन हम करके रहेंगे और यह करके हम बतायेंगे, उसमें 40 हजार मेगावाट का अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, उसके commissioning में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

उपसभापति जी, यह बात सही है 2003 का जो एक्ट है, जब यह एक्ट बनाया गया, तभी उस वक्त रिव्यु लेने की भी बात कही गयी थी। जब नया एक्ट होता है तब उसमें कुछ गलतियां रहती हैं, कुछ में कानून बनाने की रहती हैं, वैसे ही इस कानून में कुछ इस तरह का प्रावधान नहीं था, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बीजेपी के सदस्य ने यहां कहा कि वेस्ट बंगाल सरकार के जो ग्रेप्ट के कानून हैं, वहां से उस कानून को ले लिया है। इस प्रावधान में बहुत से सैक्शन ऐसे हैं जो वेस्ट बंगाल ने कुछ अच्छे काम किये हैं, उसके हमने सेम प्रॉविजन यहां ले लिया है। जैसी कि आपके दिल में शंका है कि इलेक्ट्रिसिटी ऐक्सेस जो अनाथोराइज्ड है, जो अथोरिटी दे दी है और जब उसको ज्यादा पनिशमेंट हो जायेगी, अनआथराइज्ड यूज हों, लेकिन इंटेंशन नहीं है। लेकिन जो अनआथराइज्ड

देता है, अभी मेरे पास हजारों कम्पलेंट्स आ गयी हैं कि बिजली घर में देते हैं और उस बिजली का इस्तेमाल कारखाने के लिए करते हैं। क्या उसको डिटरेंट पनिशमेंट नहीं देना चाहिए? इसके लिए यह कानून यहां बनाया है कि दस के॰वी॰ के ऊपर जो होगा, दोबारा उसको इम्प्रजनमेंट हुआ होगा, तो उसको छह महीने के लिए बिजली बिल्कुल नहीं मिलेगी और दो साल तक उसको सजा हो सकती है, यह डिटरेंस रखा है। ऐसे बहुत से केसेज हैं, जहां पर घर में बिजली है, उसका रेट कम है और बिजली फैक्टरी के लिए जाती है, तो कैसे सुधार होगा? कैसे यूटिलिटी फायदे में आ सकेगी? यह सब जो लूपहोल हैं, उनको हमने खत्म करने का प्रयास किया हैं भाटिया जी तो लीगल बैक ग्राउंड से आते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: एक मिनट सर। यह जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल परपज के लिए बिजली है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: आपकी पटना में इंडस्ट्री है, उसके बारे में मालूम है। ...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं इसकी चोरी को रोकने के बारे में कह रहा हूं। इसकी चोरी को रोकने का एक सही रास्ता यह हो जाये कि एक तो बिजली 440 वोल्टेज पर चलती है, जो थ्री फेस वाली है, जिसको पावर बोलते हैं, डोमेस्टिक वाली बिजली 220 वोल्टेज पर चलती है, उसके नीचे एक और स्टेज 110 वोल्टेज वाली है। अगर 110 को डोमेस्टिक में ले आयें; तो उससे किसी भी तरह की मशीन नहीं चल सकती है, उसको आप डोमेस्टिक में ले आइये। हमारे भारत में 110 वोल्टेज वाली टेक्नालाजी नहीं है। उसको आप ले आयें, तो मेरे ख्याल से इसका दुरुपयोग रुक सकता है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: यह अच्छा सुझाव है, इस पर विचार कर सकते हैं। महोदय, केप्टिव पॉवर प्लांट के बारे में उन्होंने कहा था। अपने एक्ट में ही जो प्रावधान किया है, अपने एक्ट में सेक्शन सात में कहा है और वहां ओपन एक्सेस दिया है। अभी लाइसेंस में उसको लाना ठीक नहीं है जो एक्ट में किया है, वह ठीक है। आपका प्रश्न ठीक नहीं होगा और केप्टिव में फिर दुबारा उसको लेकर आना ठीक नहीं होगा। श्री भाटिया जी ने सेक्शन 151 के बारे में कहा। जो प्रोविज़ो आप उसमें से पढ़कर बता रहे थे, this proviso to section 151 states that the court can take congnisance of the report of the police officer under section 173 of the Criminal Procedure Code. That means, the First Information Report is accepted in that. So, there should not be any confusion on this.

SHRI VIRENDRA BHATIA: One is 'instance' and then you say...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: That is why the court has to be

established specifically for this. So, there should not be any confusion, and those officers designated to take congnisance of this will utilise that criminal procedure that you have mentioned there.

Another thing that you have said is, whether the theft under section 373 of the Cr PC will clash with the provision of the Act. No. The Criminal Procedure Code does not fully cover all the methods of electricity theft. This amendments is aimed to define all possible methods of theft like tempering, meter tampering, etc., which have been given in the Act itself. But, if there is any...

SHRI VIRENDRA BHATIA: When the question of theft is there...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: I understand your anxiety.

SHRI VIRENDRA BHATIA: Section 379 of the IPC also comes into play.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: There is some possibility. Even abetment can also be clubbed with it. See, once he becomes a culprit, the person who is going to file a case will try to put all possible.

SHRI VIRENDRA BHATIA: I had been facing this. As an Advocate General of the State, I had been facing this. I know about so many cases. I know that in about 200 cases the proceedings were stayed because of this ambiguity. That is the thing. I have already said it.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: We will still clear it, and we will instruct as far as this case is concerned that it is possible. I am very grateful to the hon. Member that he has pointed it out. If such things occur, we will certainly instruct the SEBs that this should not be taken into account. If he comes under the I.P.C, that should be separated. But the act of the electricity theft cases should be totally treated under this. I am very happy that some of the States have really done very good work. They have appointed the courts at the district level and also wherever such difficulties are there. It is possible to bring down the losses. Once you decide to bring down the losses, then, some measures have to be taken for that. The first step, according to the Act is that we have to reorganise the State utilities. I am very happy that many States have done reorganisation of State utilities. The results have shown that those State which have done reorganisation, their losses have come down, Sir मुझे बताने में खुशी हो रही है कि

दिल्ली में बार-बार सब्सिडी के बारे में मैं कहता था। 12 सौ करौड़ रुपये सब्सिडी वहां जाती थी, लेकिन उन्होंने कुछ करेक्ट किया, बायफरकेशन किया और 1200 करोड़ राज्य के अभी बच गए हैं। मैं सदन में बार-बार यही कहता था। सर; आप मेरी तरफ देख रहे हैं कि मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करूं लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूं। क्रॉस सब्सिडी के बारे में यह बात सही है कि यह सब्सिडी गरीब लोगों को देते हैं, जिनको जरूरी है, उनको देते हैं। मैं हमारे सीपीएम के साथी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने इस बारे में चर्चा भी की थी, बहुत से लोगों ने कहा अभी पंडा जी भी कह रहे थे - सब्सिडी देने में मुझे कोई दिक्कत नही है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज छोटे-छोटे ग्रेडेशन से नीचे लाने का काम करते हैं, इसलिए "रिडक्शन" शब्द यहां यूज किया है और अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैक्शन 65 की ओर से आज भी हर स्टेट को फ्री इलैक्ट्रिसिटी देने का अधिकार है, लेकिन अगर फ्री इलैक्ट्रिसिटी देने का होगा, तो आपको पैसा युटिलिटी को पहले भरना पड़ेगा। मैंने किया था यह, महाराष्ट्र में मैं चीफ मिनिस्टर था, तब फ्री इलैक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चरिस्ट्स को दी थी, लेकिन मैंने पहले युटिलिटी को तीन सौ करोड़ का प्रोविजन करके दे दिया था, तब फ्री दे दिया था। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि कितना लोड हम ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ी दिक्कत आ गई थी उस स्टेट में लेकिन वह temporary phase ऐसा था कि उस प्रांत में अकाल था, लोगों के लिए पानी नहीं था तीन साल से, थोड़ा सा पानी आ गया। तो लोगों को बचाना जरूरी था, इसलिए स्पैशल कैस करके हमने वह किया था, नहीं तो हमेशा इस तरह से करना बहुत कठिन होता है राज्यों के लिए, क्योंकि और दूसरी priorities होती हैं।

उपसभापति जी, इस ऐक्ट के संबंध में मैं यही कहूंगा कि बहुतसी चीजों, का मैंने खुलासा कर दिया है। मेरे साथी संतोष बागड़ोदिया जी यहां कह रहे थे, अभी चले गए हैं, तो मैं उनका रिप्लाई रिकॉर्ड पर लाना भी नहीं समझता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि क्यों दूसरा करते हो, BHEL वगैरह, तो ये बातें यहां कहने की नहीं है। जो सत्य परिस्थिति है, मेरे पास जो रिपोर्ट आ गई थी, हर स्टेट के मुख्य मंत्री और पावर मिनिस्टर जो कहते थे कि हमारे ऑर्डर दे दिया है और एक-एक साल हमारा ऑर्डर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह तय हो गया, लेकिन कल बैठक हो गई, वहां तीन शिफ्ट चलाकर काम करने का BHEL ने सूचित किया है और मुझे इस बात का, मैं यह मॉनीटर करता रहूंगा, हमारे ऑफिसर्स केवल यहां ही नहीं, आपको पता नहीं यहां मंत्रालय में बैठकर ही नहीं, यह capacity additional time में करने के लिए, क्योंकि दसवीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा प्रोजैक्शन दिया था, लेकिन 56 परसेंट आपने कहा, उससे भी कम हो गया है। 50 परसेंट से ऊपर थोड़ा सा गया है, इसलिए हमें चिंता है, इसलिए खुद हमारे डिपार्टमेंट के सचिव को हम त्रिची भेज रहे हैं। ....(व्यवधान)...

श्री तपन कुमार सेन: मंत्री जी, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। यह जो स्लिपेज हुआ है, वह पूरा नहीं कर पाए हैं, तो कितना हमारा पब्लिक सेक्टर युटिलिटी कर पाया और कितनी प्राइवेट की जिम्मेदारी है, यह जरा बताइए।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: उसका पूरा जवाब मैं आपको दे दूंगा। कल जो यहां प्रश्न था ...(व्यवधान)...

श्री एस.एस.अहलुवालिया: उनको अकेले मत दीजिएगा, सदन को दीजिएगा।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सदन के पटल पर रख देंगे, जरूर रखेंगे, क्योंकि मुझे उसका फायदा है कि जो स्लिपेज हो गया है, वह हो गया है। जो नहीं होना था, उसमें बहुत राज्य हैं और इसलिए आज का यह एक छोटा सा बिल है अमेंडमेंट का, लेकिन इतनी चर्चा हो गई कि देश की इलैक्ट्रिसिटी की बात यहां आ गई। लेकिन उपसभापति जी, मुझे इसका सैटिस्फैक्शन है। ...(व्यवधान)...

श्री तपन कुमार सेन: अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजैक्ट्स के बारे में आपने नहीं बताया। ...(व्यवधान)...

श्रीमती माया सिंह: (मध्य प्रदेश) मैं भी यही पूछना चाहती थी।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: आप भी पूछना चाहती थीं?

श्रीमती माया सिंह: मैं यह पूछना चाहती थी कि जो पांच अल्ट्र मेगा पावर प्रोजैक्ट्स हैं, जो काफी समय से लम्बित पड़े हैं, उनकी स्थिति क्या है?

श्री सुशील कुमार शिन्दे: मैं बता रहा हूं। उपसभापति जी, देश में बिजली कम है, ऐसा कहकर भारत सरकार ने अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजैक्ट्स करने का यह निर्णय ले लिया। एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजैक्ट 4000 मेगावॉट का है और उसकी कीमत 16 से 20 हजार करोड़ रुपए की है, यानी साढ़े तीन-चार बिलियन डॉलर की एक की कीमत है और मुझे खुशी इस बात की है कि जो प्रयास हमने किया था, एक साल के अंदर, दो अल्ट्रा मेगा प्रोजैक्ट जो मुंद्रा और सासन, एक है पिटहैड और दूसरा है कोस्टल मुंद्रा। एक की प्रति यूनिट कीमत है 1 रुपए 19 पैसे जो सासन का है, जो पिटहैड है और दूसरा जो कोस्टल मुंद्रा है, बाहर से कोयला लाकर करने का है, उसकी कीमत है 2 रुपए 40 पैसे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है कि 1 रुपए 19 पैसे प्रति यूनिट बिजली, इतनी सस्ती बिजली बिलकुल नहीं मिलती है, यह हाइड्रो से भी आजकल नया प्रोजैक्ट किया जाए, तो ढाई रुपया या तीन रुपया होता है ग्रेडेशन से, बाद में यह कम हो जाता है। भाखड़ा नांगल से आज इतने साल होने के बाद ही 13 पैसे में एक यूनिट बिजली मिलती है, क्योंकि उसे इतने साल तक रुकना

पड़ेगा, लेकिन एक रुपए 19 पैसे में अभी अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स से 25 साल के लिए यह बिलिंड्रग प्रोसिजर किया है। इसमें से अभी दो गए हैं, दूसरे दो अभी आ रहे हैं, एक आन्ध्र का है और दूसरा झारखंड का है, कृष्णा पट्नम।

श्री तपन कुमार सेन: आपने NTPC क्यों इतना ज्यादा कोट किया है, 1.30 रुपए का खर्चा आता है, आपने यह सब दिया।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: देखिए, मंत्री ...(व्यवधान)..

SHRI TAPAN KUMAR SEN: How did they quote it? I would like to know whether it is their own decision or your own decision.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: NTPC is an independent body. They do business. So, they will have to find out this thing accordingly. For that only competition is there. Unless there is competition, we will not know where we stand. Otherwise, those who are in the field will charge it and they will say that this is the lowest price. This is the way we come to know that the price can come down.

SHRI TAPAN KUMAR SEN: But will you not question the prodence? When per unit cost is Rs.1.13, I would like to know whether that prudence would be questioned or not. If it is their decision...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, he has explained it.

श्री तपन कुमार सेन: उसमें तो एलाउ कर दिया है,...(व्यवधान)...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: There must be many...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: I think that is a matter to be inquired.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: No, why should we inquire? If they had come below Rs. 1.19, they would have got it. They have not got it. It is their business. why should we inquire into it? If it is affordable to them, will they come or not? That is all.

श्री रुद्रनारायण पाणि: सरकार का पैसा लगा हुआ है।...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार शिन्दे: वह तो एटोनोमस बॉडी है।...(व्यवधान)... वह तो नवरत्न बॉडी है।

मैंने कन्ट्रैक्ट उसी के लिए बोला है। राज्यों का काम कन्ट्रैक्ट करना है। भारत सरकार की युटिलिटी में नहीं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठिए, बैठिए।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: मंत्री निर्णय नहीं लेता है, बल्कि बोर्ड लेता है।...(व्यवधान)...You know everything but you want to...(*Interruptions*)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: But it is under Your supervision.

SHRI SUHILKUMAR SHINDE: Tapanji, yes, my supervision is there, but these things are not...

श्री उपसभापति: मंत्री जी, आप समाप्त कीजिए।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Wrong economic and managerial decisions are there. That must come under scrutiny. Otherwise, you are giving them a cakewalk.

MR. DEPUTY CHAIRMAN; No, no, Mr. Tapan Sen. This can't go on. There cannot be cross-talks. please...(*Interruptions*)... नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, चेयर को एड्रेस करना है।...(व्यवधान)... आज जो चाहे पूछें, आप दोनों में बातें होती रहती हैं, यह सब ठीक नहीं है।

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: This is very easy. Tomorrow, if my utility goes into loss and becomes zero, Mr. Tapan will only ask, 'you were supervising this utility, how did it go into loss' It is not my duty to manage properly? It was not affordable for them. I inquired. It was not affordable for them at that stage. They have not accepted because they are doing business in Nigeria. They are doing business in Sri Lanka.

So, it is good. Sir, he is my friend, he must get all the information on what NTPC is doing, (*interruptions*)

श्री सुशाल कुमार शिन्दे: सर, इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है कि एक-एक ...(व्यवधान)... उपसभापति जी, मैं इस सदन में सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सब मिलकर इस देश को कैपेसिटी एडिशन दें। मैं पूरे विश्वासपूर्वक आपसे कहता हूं कि 2012 तक हम हर घर में बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। हम पार्टी से ऊपर, स्टेट से ऊपर जाकर यह करेंगे क्योंकि आज हम सत्ता में हैं और कल आप रहेंगे, परसों कोई दूसरे रहेंगे, लेकिन देश की जो गरीब जनता है, ...(व्यवधान)...

श्री सूरजनारायण पाणि: लालू जी को उनका चुनाव चिन्ह बदलना होगा। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठिए, पाणि जी। ...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सर, इसका मतलब 2012 तक ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मतलब कुछ भी नहीं है। आप बैठिए ।...(व्यवधान)... मतलब की जरूरत नहीं है। आप बैठिए, बैठिए।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: सर, अगर इस देश की जनता ने 2012 तक हमें सत्ता पर रहने के लिए दिया तो हम क्या करेंगें ? हम इस सत्ता पर रहेंगे। अगर पोलिटिकल स्पीच करनी है तो मैं भी कर सकता हूं But, I do not want to do. उपसभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि यहां पर इतनी अच्छी तरह से डिसकशन हो गया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अजय मारू: उपसभापति जी, एक मिनट ...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार शिन्दे : अच्छा पूछ लीजिए।

श्री उपसभापति: उन्होंने आपकी प्रशंसा भी की है कि आपने अच्छा कहा है।

श्री अजय मारू: आपने जवाब दिया। उपसभापति जी, पावर ग्रिड कार्पोरेशन, पावर फाइनेंस कार्पोरेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में आपने जवाब दिया कि जितना ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य है, वह उसे सौंपा है। झारखंड में अभी भी 20,000 गांव ऐसे है? जहां पर विद्युतीकरण का कार्य है, वह उसे सौंपा है। झारखंड में अभी भी 20,000 गांव ऐसे हैं, जहां पर विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। आपने अपने जवाब में लिखा है कि 2007-08 में 2720 गांवों का विद्युतीकरण होगा। उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन यदि इसी रफ्तार से कार्य हुआ तो झारखंड में अगले नौ वर्षों में कार्य पूरा होगा। आपका जो एश्योरेंस है कि 2009 तक पूरा हो जाएगा, यह नहीं होगा। मैं आपसे एश्योरेंस चाहता हूं कि 20,000 गांवों में विद्युतीकरण का जो काम है, उसे कैसे पूरा करेंगे।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: उपसभापति जी, मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी यहां आए थे। मैंने उनसे पूरा डिसकस किया था। झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर लेना तय किया है। जैसे ही यह पैसा आ जाएगा, वह काम हो जाएगा। इसमें नौ, दस या ग्यारह साल नहीं लगेंगे। हमने जो तय किया है, वह उसमें हो जाएगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the question is:

That the Bill further to amend the Electricity Act, 2003, be taken into consideration.

The motion was adopted

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 21 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted

STATEMENTS BY MINISTERS—*Contd.*

Addition of New Districts In Uttar Pradesh under National Rural Employment Guarantee Act, 2005 and Status of Implementation of National Rural Employment Guarantee Act, 2005

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में नए जिलों को शामिल किया जाना और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में वक्तव्य सदन पटल पर रखता हूं।

Status of Implementation of Recommendations contained in the Fifteenth Report of The Department-related Parliamentary Standing Committee on Coal and Steel

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (DR. DASARI NARAYAN RAO): Sir, I lay this statement on the status of implementation of recommendations contained in the Fifteenth Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Coal and Steel.